THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN) : Assam State Industrial Development Corporation (ASIDC) was granted a letter of Intent dated 25-1-91 for a Gas Cracker Project in Assam. Work on setting up of the project can start after the Corporation has selected its joint collaborator, arranged funds and prepared a detailed feasibility report for the project.

Compensation claims of Bhopal Gas Victims

1188. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the number of compensation claims of Bhopal Gas Victims settled during the last two months;

(b) the reasons for slow progress ; and

(c) the measures Govenment propose to take to expedite the settlement of claims ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN) : (a) to (c) No payment against compensation claims has been made during the last two months due to a few Deputy Commissioners joining duty. Work will progress speedily when all the 40 Deputy Commissioners take up position.

भोपाल गैस पीड़ितों को राहत राशि का वितरण करने में विलम्ब

1189. श्री अनन्त राम जायसवाल :
श्री एन० ई० बलराम :
डा० जैड० ए० अहमद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल गैस पीड़ितों में राहत राशि के वितरण के लिए दिशा-निदश निर्धारित करने में सरकार द्वारा किए जा रहे विलम्ब के कारण राहत राशि के वितरण का कार्य रुका हुआ है, यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई समय सीमा निर्धारित की थी, यदि हां, तो इस संबंध में वह समय सीमा क्या थी, वह कब समाप्त हो गई थी तथा उसका पालन न किये जाने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि भोपाल गैस पीड़ितों के मुआवजे संबंधी दावों का निपटारा करने के लिए 3 फरवरी, 1992 तक कम से कम 40 दावा अधिकरणों द्वारा कार्य करना आरंभ हो जाना चाहिए था ।

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अभी तक बहुत कम दावा अधिकरण ही खोले गए हैं तथा जिन न्यायालयों ने कार्य करना आरम्भ कर भी दिया है उनके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अभाव में वास्तव में कोई काम नहीं हैं; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस राहत राशि का वितरण आगामी मार्च में कर दिया जाये ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।